हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 21 अगस्त 2025, समय 1305 (05 मिनट)

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्ट्रीम केसिस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया। कमाने के बाद में सुसाइट के तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन में तो इसको पब्लिक हैल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिस्आर्डर की तरह से इसको घोषित किया है तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करें, इनकरेज करें और जो समाज के लिए हानिकारक हो उसको रोके ।

****

भिवानी के ढ़ाणी लक्ष्मण में बेटी मनीषा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में सामाजिक लोगों, ग्रामीणों, परिजनों, प्रशासन व पुलिस ने दी मनीषा को अंतिम विदाई दी।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि महानिरीक्षक राजश्री भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। उन्होंने मनीषा के परिजनों को सांत्वना दी।

मामले की जांच को लेकर आंदोलन बीती रात ही समाप्त हो गया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एम्स से पोस्टमार्टम करने व सीबीआई जांच की मांग पूरा होने से आंदोलनकारी संतुष्ट हैं।

लोहारु के एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि स्थानीय जनभावनाओं अनुसार मामले की सीबीआई जांच करवाई जा रही है। सीबीआई जांच में कुछ अलग मिलता है तो राज्य सरकार दोषियों को सजा दिलाएगी।

****

भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को देश हित में बताया है ।

हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा बिल की कॉपी फाड़ने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह व कागज को आसन की तरफ फेंकने की घटना की निंदा की और कहा कि यह कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बचाने का एक निन्दनीय प्रयास है।

श्री बडौली ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश इन तीनों विधेयकों का सीधा-सीधा मकसद है कि अब सरकार जेलों से नहीं चलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में पेश किए तीनों विधेयक को देशहित में बताते हुए पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि विधेयक के अनुसार कोई मंत्री लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रहता है, जिसकी सजा पांच साल या उससे अधिक हो सकती है, तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन हटा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन के बाद वह व्यक्ति खुद-ब-खुद मंत्री पद से हटा हुआ माना जाएगा। अगर इन 30 दिनों के अंदर सजा का प्रावधान हट जाता है, या सजा 5 साल से कम हो जाती है या फिर सजा पर अदालत रोक लगा देती है तो फिर से उन्हें पद पर लाया जा सकता है।

श्री बड़ौली ने कहा कि विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना होगा। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक कदम शासन को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने में मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तीनों बिल अलग-अलग इसलिए लाए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के नेता के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

****

हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रखने का निर्णय लिया है। ताकि अत्याधिक बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 7 जिलों के 188 गांवों के किसान फसल क्षति के दावे दर्ज कर सकें।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कल शाम को जिला उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, हिसार के 85 गांव प्रभावित हुए हैं, इनमें बाद भिवानी के 43, रोहतक के 21 और पलवल के 17 गांव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चरखी दादरी के 13 गांव, रेवाड़ी के 7 गांव और सिरसा के 2 गांवों के लिए भी पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि जिला राजस्व अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों का सत्यापन किया जाएगा और आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा।

प्रवक्ता ने किसानों से अपनी फसल क्षति का पंजीकरण जल्द से जल्द कराने की अपील की है।

****